रिहन्द जल विद्युत परियोजना से मध्य प्रदेश को विद्युत

998. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की रिहन्द जल विद्युत परियोजना के विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का 15 प्रतिशत हिस्सा है और उस राज्य को अपना हिस्सा पिछले कई वर्षों से नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को उसका हिस्सा कब दिलाया जाये ; और उस राज्य को पहले न दिये गये हिस्से की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान मध्य प्रदेश के हजारों गरीब आदिवासी विस्थापित हुए थे और उन्हें अब तक सही प्रकार से बसाया नहीं गया है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) रिहन्द परियोजना की विद्युत की भागीदारी के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच हुए समझौते में यह व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को रिहन्द परियोजना की विद्युत में से उसके हिस्से की सप्लाई न कर पाने की अवस्था में पारस्परिक सहमति से इस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मामले का समाधान उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा आपसी सहमति से किया जाना है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

999. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने राजगढ़ झाबुआ, गुना और ग्वालियर में स्थापित की जाने वाली चार गैस-आधारित विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने 27 अक्तूबर 1990 के अपने पत्र के माध्यम से तत्कालीन केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से यह अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली ग्वालियर परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जाये, यदि हां तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने राजगढ़ झाबुआ, गुना और ग्वालियर में उपस्थित 4 गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए अक्तूबर 1988 में प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। प्रस्तावों में प्रत्येक स्थान पर 450 मे०वा. (3-100मे०वा. गैस टर्बाइन+1×150प.वा. स्टीम टर्बाइन) प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इन स्कीमों के लिए गैस की उपलब्धता और जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई हैं। इसलिए के. वि.प्रा. में इन परियोजनाओं पर कारवाई नहीं की जा रही हैं और तदनुसार 17-11-89 को मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को भी सूचित कर दिया गया है। तदोपरान्त ग्वालियर जीटीसीसी 817 मेवा. (4×131 3मेवा. गैस टर्बाइन+21×46मेवा.स्टीम

टर्बाइन) की स्थापना के लिए अगस्त, 1990 में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसकी के.वी.प्रां में जांच की जा रही है। इस परियोजना के लिए एचबीज पाइप लाइन से गैस विद्युत सप्लाई किए जाने की परिकल्पना की गई है। के.वी.प्रां. में स्कीम का मूल्यांकन किए जाने पूर्व कुछ अपेक्षित निवेश यथा गैस की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, केन्द्र और राज्य से पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से स्वीकृति और विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 29 की अनुपालना आदि सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

(ग) ऊर्जा मंत्री को संबोधित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिनांक 27 अक्तूबर 1990 के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केन्द्रीय क्षेत्र में ग्वालियर जी टी सीसी स्थापित किए जाने हेतु इसको शीघ्र तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किए जाने का, अनुरोध किया गया है उपरोक्त निवेश सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् ही के.वि.प्रां. में स्कीम का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह के एकक 5 और 6 का स्थापित किया जाना

1000. श्री अजीत जोगी :
कुमारी सईदा खातून :

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह के एकक सं. 5 और 6 की स्कीम योजना आयोग को वित्तीय स्वीकृति के लिए 17 जून 1991 को भेजी है ;

(ख) क्या उसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ग) इस स्कीम को वित्तीय स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी और कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा और उसके कब तक पूरा होजाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने संबंधी प्रश्न को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) स्कीम को स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए योजना आयोग में कार्रवाई की जा रही है।

Request for supply of Natural Gas to Goa for Generation of Power

1001. SHRI JOHN. F. FERNANDES: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have received any request from Goa Government or other agencies for the supply of Natural Gas to Goa to generate electric power from gas turbine in view of an acute power shortage in Goa;

(b) if so, how many proposals have been received and the names of the agencies; and

(c) what has been Government's response to these proposals?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (c) Yes, Sir. The matter of supply of gas to Goa is also under examination by an Inter-ministerial Group examining the feasibility of a "Southern Gas Grid".